RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 2021; 6(3):55-61
ISSN: 2455-3085 (Online)
https://doi.org/10.31305/rrijm.2021.v06.i03.010
Research Paper
Double Blind Peer Reviewed/Refereed Journal
https://www.rrjournals.com/

विमुद्रीकरण के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर के फुटकर व्यापारियों के विशेष संदर्भ में)

[1]Dr. Gajpal L.S. and [*2]Yadu Akhil

[1]Associate Professor & HOD, SOS Sociology and Social Work. Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, C.G.
[2]Research Scholar, Department of Sociology, Govt. J.Yoganandam Chhattisgarh College, Raipur, C.G.

ABSTRACT

विमुद्रीकरण एक प्रकिया हैं, जिसमें शासन द्वारा प्रचलित मुद्रा अथवा चलित मूल्यवान खनिजों को कानूनी निविदा के आधार पर सार्वजनिक दोहन हेतु अमान्य कर दिया जाता हैं, यह प्रकिया तब अपनाई जाती हैं। जब एक निश्चित मुद्रा मूल्य, राष्ट्र में नियमित उपयोग में नही रहती, अथवा एक नई मुद्रा परिसंचरण में आती हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम सम्बोंधित करते हुए, 8 नवम्बर 2016, को रात 8:30 बजे विमुद्रीकरण की घोषणा की गई। जिसके तहत् मध्य रात्रि से 500 रूपयें एवं 1000 रूपयें के नोट भारत में कानूनी रूप से अमान्य (चलन से बाहर) घोषित कर दिए गए। स्पष्ट हैं कि उच्च मुल्य वर्ग की मुद्रा को प्रचलन से बाहर करने की प्रकिया अर्थशास्त्र की भाषा में विमुद्रीकरण (डिमॉनेटाइजेशन) कहलाती हैं। इस अध्ययन का लक्ष्य फूटकर व्यापारियों के रोजमर्रा के व्यापार में आने वाली समस्या एवं विमुद्रीकरण से नवीन विचारों में उत्पन्न, होने वाले परिवर्तनों को समझना एवं इसके निवारण हेतु प्रयास करना हैं। यह शोधपत्र विमुद्रीकरण के दौरान सत्र 2016–17 में शोधार्थी द्वारा किए एम.फिल उपाधि हेतु (लघु शोध प्रबंध) के प्राथमिक तथ्यों पर आधारित हैं।

Keywords: *विमुद्रीकरण, फुटकर व्यापारी*

Article Publication

Published Online: 15-Mar-2021

[*]Author's Correspondence

Yadu Akhil

Research Scholar, Department of Sociology, Govt. J.Yoganandam Chhattisgarh College, Raipur, C.G.

akhilyadu1592[at]gmail.com

© 2021The Authors. Published by *Research Review Journals*

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

1. प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता हैं, कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम तिमाही में दिनांक 31 मार्च 2016, तक 500 रूपयें एवं 1000 रूपयें के नोटों का संचलन कुल मौद्रिक अनुपात का 86.4 प्रतिशत् था, जिनका कुल मुल्य लगभग 14 अरब डॉलर हैं। इस मुल्य का अधिकांश हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन में विधि देने हेतु, नकली नोटों के रूप में, एवं कालेधन के रूप में व्याप्त थी। अतः 8 नवम्बर 2016, को विमुद्रीकरण की घोषणा करके सरकार ने, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले सभी तीन मुद्दों से निपटने का प्रयास किया, अर्थात् एक समांतर अर्थव्यवस्था, नकली मुद्रा परिसंचरण, एवं आतंक वित्तपोषण। बाबा साहेब अम्बेडकर की 1923 में पी.एच.डी. के डॉक्टरेट थीसिस ''द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीः इट्स ऑरिजन एण्ड इट्स सोल्यूशन''[1] पर हैं। इस थीसिस में उन्होनें विमुद्रीकरण के विषय में कहा हैं कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए प्रत्येक 10 वर्षो में नोटों को बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। सरकार ने जो विमुद्रीकरण की घोषणा के पश्चात जो 2000 रूपयें के बड़े नोट का परिसंचरण किया उसने मुद्रा की कमी में सहायता करने के बजाय् छोटे खरीदारों को बड़े नोट के उपयोग के लिए छोड़ दिया। जिसे छोटे व्यापारी विनिमय करने में असमर्थ थे। जिनके पास नकदी थी, वे इसे समझदारी से प्रयोग कर रहे थें। क्योंकि वे नकद निकासी के लिए बैंकों में लंबी कतार में खड़े होने की मुश्किलों से गुजरना नही चाहते थें। जिन छोटे व्यापारियों को जिनके पास रख रखाव की क्षमता नही हैं अथवा वे जो परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु प्रतिदिन वस्तुओं की ब्रिकी पर निर्भर हैं, उन्हे विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के क्रियान्वयन की अपेक्षा बाजार में नकद व चिल्हरों की समस्या ने अधिक ग्रसित किया। भारत में अधिकांशतः 95 प्रतिशत् नागरिक लेनदेन हेतु नगद का प्रयोग करतें हैं। अर्थव्यवस्था में फुटकर व्यापारियों के साथ जुड़े लेनदेन की आवृत्ति और मात्रा में नकदी

लेनदेन की आवश्यकता होती हैं, इस प्रकार, इन क्षेत्रों को विमुद्रीकरण प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद हैं, और परिसंचरण में नए बड़े नोटों की शुरूआत करने से चिल्हरों की समस्या उत्पन्न होने की भी संभावना हैं। जो इन क्षेत्रो में संलग्न व्यवसायियों के आजीविका व दिनचर्या को प्रभावित करता हैं।

1.2. विमुद्रीकरण की घोषणा

8 नवम्बर 2016, को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की कि 9 नवम्बर 2016, से 500 रूपयें व 1000 रूपयें के बैंक नोट कानूनी निविदा के रूप में अमान्य होगें तथा 500 रूपये के पुराने नोटों की जगह नए 500 रूपयें एवं 1000 रूपयें के पुराने नोट की जगह 2000 रूपयें के नए बैंक नोट 10 नवम्बर को सार्वजनिक रूप से प्रचलन में मान्य होगें। इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता हैं। जिसमें उच्च मुल्य के चलित मुद्रा को बंद करके उनकी जगह नई मुद्रा का प्रचलन कर दिया जाता है।

1.3 भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास

2016 में भारत में विमुद्रीकरण का यह तृतीय प्रयास था। भारत में विमुद्रीकरण क पहला प्रयास वर्ष 1946 मे किया गया था। वर्ष 1946 में भारत ब्रिटेन का औपनिवेशिक देश था तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था, जनवरी 1946 में उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को बंद किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर सी.देशमुख ने कर चोरी के कारण 10000 करोड़ रूपयें की ब्लैक मनी को समाप्त करने के लिए 1000 रूपयें तथा 10000 रूपयें के नोट को समाप्त करने की घोषणा की। दुसरा प्रयास जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 10000, 5000, तथा 1000 रूपयें के नोटों को प्रचलन से हटाने का काम किया।[2]

2. अध्ययन विषय का समाजशास्त्रीय महत्व

विमुद्रीकरण के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अभी तक कोई विशेष योजना का निर्माण नही किया गया हैं। जिससे दैनिक आय प्राप्तकर्ता (फूटकर व्यापारी) को उचित राहत प्राप्त हो सके। विमुद्रीकरण, मौद्रिक नीति के अंतर्गत कालेधन की समाप्ति को लेकर चलाया गया शासकीय प्रयास हैं। यद्यपि विमुद्रीकरण की नीति का प्रयोग हमें इतिहास के अनके घटना क्रमों से स्पष्ट होते हैं, उदा. विजय राजवंशों द्वारा पराजित राजवंशों के मुद्राओं को समाप्त कर अपनी संस्कृति में प्रचलित नए मुद्रा का चलन करना।

विमुद्रीकरण का समाज पर सकरात्मक एवं नकरात्मक प्रभाव इस नीति के क्रियान्वयन पर निर्भर करता हैं, जोकि पूर्णतः राजनैतिक नियंत्रण पर आधारित हैं। इस नीति के क्रियान्वयन के दौरान फुटकर व्यापारियों पर आने वाली सामाजिक समस्या का अध्ययन करना, इस समस्या के निवारण एवं भविष्य में आने वाले अन्य किसी आर्थिक गतिविधियों के पूर्व सामाजिक कार्यप्रणाली को स्थायी बनाने हेतु संचरणात्मक पथ, प्रभावित नगरिकों पर शासन द्वारा अनुकुलन की स्थिति उत्पन्न करना, जनसमान्य को मौद्रिक नीतियों के सकरात्मक पहलुओं एवं वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणाली हेतु जागरूक करना इस शोध का मुख्य तत्व हैं।

3. शोध साहित्य का पुनरावलोकन

चोकोबा एवं ईजू (2012)[3] का शोध नाइजिरिया के विमुद्रीकरण के प्रभाव को दर्शाता हैं, उन्होंने अपने अवलोकन में पाया कि विमुद्रीकरण के दौरान 68.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समस्या के रूप में बैंको में लगी लंबी कतारों को, 28.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार को समस्या के रूप में, 2.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने घर अथवा कार्यस्थल से बैंक की दूरी को समस्या के रूप में बताते हैं। नगद निकासी से सम्बन्धित अवलोकन में उन्होने पाया कि 51 प्रतिशत नगद निकासी ए.टी. एम से 33.6 प्रतिशत नगद निकासी बैंक काउन्टर से, तथा 13.6 प्रतिशत चेक द्वारा नगद निकासी नाइजिरिया में विमुद्रीकरण के दौरान हुआ। **माधुरी, श्रीनिवास राजू एवं निलिमा (2016)**[4], **राधाकृष्ण (2016)**[5] ने अपने शोधपत्र में विमुद्रीकरण के पश्चात् भारतीय कैशलेस व्यवस्था के विषय में तथ्य प्रस्तुत किए हैं। **एम.चलादुराई एवं वी. सोरनागणेश (2016)**[6] का शोधपत्र भी इसी संदर्भ पर आधारित हैं। भारत में विमुद्रीकरण पर शोध में दो प्रकार के अध्ययन शामिल हैं, एक पक्ष अतीत में उठाए गए लोगों के साथ वर्तमान विमुद्रीकरण उपाय की तुलना करता हैं। ऐसे अध्ययनों में **राजकुमार एवं शेट्टी (2016)**[7] तथा **नाग (2016)**[8] द्वारा दिया गया विवरण महत्वपूर्ण हैं। दूसरा पक्ष सैद्धांतिक रूप से विमुद्रीकरण की पुष्टि करता हैं, जिसमें **दासगुप्ता (2017)**[9] तथा **वाकिन्स (2017)**[10] का अध्ययन सर्वोपरि हैं। हलांकि दासगुप्ता का अध्ययन अनौपचारिक क्षेत्र में विमुद्रीकरण के प्रभाव की विवेचना नही करता। वहीं वाकिन्स का अध्ययन औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र के एक–दूसरे के संलग्नता के साथ विमुद्रीकरण के प्रभाव की विवेचना करता हैं।

सम्पूर्णा नंद मेहता (2016)[11] का अध्ययन मुम्बई महानगर के छोटे व्यवसायियों/फूटकर व्यापरियों पर विमुद्रीकरण के नकरात्मक प्रभाव पर केन्द्रित हैं। **प्रशांतजी तंदाले, ए.टी.गायकवाड, एवं आर.ए. मराठे (2017)**[12] का अध्ययन कोल्हापुर (मुंबई) के इंटरनेट बैंकिंग पर केन्द्रित हैं, जिसमें विमुद्रीकरण के पश्चात् इंटरनेट बैंकिंग के विषय में अध्ययन को दर्शाया गया हैं। **डेविड लिविंगस्टोन (2016)**[13], **दुर्गा एवं दुर्गादेवी (2016)**[14] तथा **सीतारामा मुर्ति (2016)**[15] ने विमुद्रीकरण के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव की विवेचना में अपने शोधपत्र प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त **पारूल महाजन (2017)**[16], **के.भारती (2017)**[17], **प्रीति(2017)**[18], **सुरप्रित सिंग (2017)**[19], **दिया राय (2016)**[20], **अमोल दीपक नेरकर (2016)**[21], **जय बंसल (2017)**[22], **अरविन्द्र कौर कोहलोन (2017)**[23], **समरवीर सिंग राठौर (2017)**[24], **गीता रानी (2016)**[25], **एस.बालामुर्गन् एव ंबी.के.हेमलता (2016)**[26], **नितीन कुमार एवं शर्मिला (2016)**[27] तथा **पवन कल्याणी (2016)**[28] के शोधपत्र भारत में विमुद्रीकरण के अलग–अलग क्षेत्र से सम्बन्धित कारण, प्रभाव, उपयोगिता, विशेषताएं आदि पर आधारित हैं।

4. अध्ययन का उद्देश्य

- फुटकर व्यापारियों पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का आकलन करना
- यदि इस प्रभाव से व्यापार में नुकसान हुआ हैं तो उसका आकलन करना
- फुटकर व्यापारियों द्वारा विमुद्रीकरण के दौरान प्रचलित अनिभव उपायों का पता लगाना

5. अध्ययन की सीमाएं

- अध्ययन का क्षेत्र, अनुसंधान की सबसे बड़ी सीमाएं हैं, यह अध्ययन केवल रायपुर नगर तक ही सीमित हैं, जिससे भारत की समस्त स्थिति को स्पष्ट नही किया जा सकता।
- अध्ययन के लिए चयनित उत्तरदाता अधिकांशतः अशिक्षित व आंशिक रूप से शिक्षित हैं, जो केवल जीवन निर्वाह एवं पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए व्यवसाय करते हैं। यह अध्ययन उन लोगों का प्रतिनिधित्व नही करता जिन्होंनें व्यवस्थित व नियमित व्यवसाय स्थापित किया हों।
- यह अध्ययन केवल फुटकर व्यापारियों पर ही आधारित व्यक्तिगत राय एवं सुझाव पर दृष्टिगोचर हैं। अतः विमुद्रीकरण के प्रभाव को समस्त जनसंख्या पर आधारित नही माना जा सकता।

6. शोध संरचना, पद्धितिशास्त्र एवं निदर्शन

(प्राथमिक आंकड़े, निदर्शन आकार, शोध उपकरण एवं प्रविधि)

अध्ययन हेतु संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची (उपकरण) का प्रयोग शोध निर्देशक के परामर्श से बनाए गया हैं, तथा व्यक्तिगत (अनौपचारिक) साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग कर प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। अध्ययन क्षेत्र के लिए रायपुर नगर के प्रत्येक जोन से एक वार्ड का चयन दैव निदर्शन के लॉटरी प्रणाली का प्रयोग कर कुल 8 वार्ड को चुना गया हैं। एवं उत्तरदाताओं के चुनाव के लिए कुल 8 वार्ड के चिन्हित् 517 फुटकर व्यापारियों में से 124 फुटकर व्यापारियों का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से किया गया हैं, जो कि समग्र का 23.9 प्रतिशत् हैं।

उत्तरदाता के रूप में फुटकर व्यापारियों को कुल 5 श्रेणी में विभाजित किया गया हैं जिसमें कच्चे खाद्य पदार्थ विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय में सब्जी व्यवसायी, फल व्यवसायी, एवं बायलर (चिकन) दुकान को सम्मिलित किया गया हैं। निर्मित खाद्य पदार्थ विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय में पान ठेला, चाय ठेला, चाट/दाबेली ठेला, फास्ट फूड, बिरयानी सेंटर, जूस सेंटर को सम्मिलित किया गया हैं। यांत्रिकी पुर्जे सुधार सम्बन्धित व्यवसाय में घड़ी रिपेरिंग सेंटर, सायकल रिपेरिंग सेंटर, टायर/ट्यूब फीटिंग, ऑटो मोटर सायकल रिपेरिंग सेंटर, सम्मिलित हैं। दैनिक उपभोग वस्तु विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय में प्लास्टिक वस्तु विक्रेता, कपड़ा विक्रेता, चश्मा विक्रेता, चूड़ी विक्रेता, सीडी/पर्स विक्रेता, सम्मिलित हैं। सेवा सम्बन्धित व्यवसाय में सेलुन दुकान, टेलर दुकान, मोची दुकान को सम्मिलित किया हैं। जो अध्ययन् इकाई (फूटकर व्यवसायी) को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता हैं।

क्रमांक	व्यवसाय	निदर्शन आकार
1.	कच्चे खाद्य पदार्थ विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय	30
2.	निर्मित खाद्य पदार्थ विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय	49
3.	सड़क किनारे यांत्रिकी कल पुर्जे सुधार सम्बन्धित व्यवसाय	19
4.	दैनिक उपयोगी वस्तु विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय	12
5.	सेवा सम्बन्धित व्यवसाय	14
	योग	**124**

द्वितीयक आंकड़े – अध्ययन हेतु द्वितीयक आंकड़ों की प्राप्ति सामाचार पत्र, मासिक पत्रिका, शोध पत्रिका, व इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया गया हैं।

अध्ययन से प्राप्त आंकड़ो का तालिकानुसार विवरण

तालिका क्रमांक . 01 जनसंख्यिात्मक विश्लेषण

लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत्
पुरूष	105	84.6
महिला	19	15.4

आयु	आवृत्ति	प्रतिशत्
20–30 वर्ष	27	21.7
30–40 वर्ष	39	31.4
40–50 वर्ष	33	26.6
50–60 वर्ष	17	13.8
60–70 वर्ष	08	6.5

मासिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत्
5000–6000 रू.	24	19.4
6000–7000 रू.	25	20.2
7000–8000 रू.	35	28.2
8000–9000 रू.	16	12.9
9000–10000 रू.	14	11.2
10000 रू. से अधिक	10	8.1

यह प्राथमिक आंकड़े साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अनौपचारिक साक्षात्कार पद्धति के प्रयोग से प्राप्त की गई हैं, जो कि अध्ययन से सम्बन्धित उत्तरदाताओं (फुटकर व्यापारी) के व्यक्तिगत तथ्यों पर आधारित हैं।

तालिका क्रमांक 02

विमुद्रीकरण के पूर्व एवं विमुद्रीकरण के पश्चात् फुटकर व्यापारियों की प्रतिदिन प्राप्त आय की स्थिति का विश्लेषण

फुटकर व्यापारियों के प्रतिदिन प्राप्त आय	विमुद्रीकरण के पूर्व	विमुद्रीकरण के पश्चात्	विचलन प्रतिशत् का अंतर	प्रमाप विचलन
100 रूपयें तक	**36**	**41**	**133.88 ↑**	**3.535534**
100 – 200 रूपयें तक	**20**	**52**	**260 ↑**	**22.62742**
200 – 300 रूपयें तक	**20**	**20**	=	**0.0**
300 – 400 रूपयें तक	**20**	**09**	**222.22 ↓**	**7.071068**
400 – 500 रूपयें तक	**16**	**2**	**800 ↓**	**9.899495**
500 – 600 रूपयें तक	**8**	**0**	**800 ↓**	**5.656854**
600 से अधिक	**4**	**0**	**400 ↓**	**2.828427**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हैं कि उपभोक्ताओं का विमुद्रीकरण पश्चात् खर्च में परिवर्तन आया हैं जिसका प्रभाव फुटकर व्यापारियों व्यापारियों के आर्थिक स्थिति पर पड़ा हैं, तथा उनके प्रतिदिन आय में परिवर्तन आया हैं। सारणी का विश्लेषण करने से प्राप्त होता हैं, कि फुटकर व्यापारियों को विमुद्रीकरण पश्चात् चिल्हरों की समस्या के कारण आमदनी में परिवर्तन आया हैं। तथा अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ हैं कि विमुद्रीकरण पश्चात् कैशलेस पॉलिसी एवं डिजिटलाइजेंशन से परिचित नही होने से आमदनी में कमी आयी हैं।

तालिका कमांक 03

विमुद्रीकरण से भारत एक नगदरहित समाज के रूप में व्याप्त होना

क.	व्यवसाय	हां	प्रतिशत्	नही	प्रतिशत्
1	कच्चे खाद्य पदार्थ विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय	04	13.33	26	86.64
2	निर्मित खाद्य पदार्थ विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय	10	20.40	39	79.60
3	यांत्रिकी पुर्जे सुधार सम्बन्धित व्यवसाय	3	15.78	16	84.22
4	दैनिक उपभोग वस्तु विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय	3	25	9	75
5	सेवा सम्बन्धित व्यवसाय	3	21.42	11	78.58

(स्त्रोत् – प्राथमिक आंकड़े) सारणी से स्पष्ट हैं कि **(23)** फूटकर व्यापारी विमुद्रीकरण पश्चात् कैशलेस समाज के रूप में व्याप्त होने के पक्ष में हैं तथा **(101)** कैशलेस समाज के पक्ष में नही हैं।

तालिका कमांक 04

पीओएस मशीन, एवं मोंबाइल बैंकिंग के पक्षधर

क.	व्यवसाय	हां	प्रतिशत्	नही	प्रतिशत्
1	कच्चे खाद्य पदार्थ विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय	01	3.33	29	96.67
2	निर्मित खाद्य पदार्थ विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय	3	6.12	46	93.88
3	यांत्रिकी पुर्जे सुधार सम्बन्धित व्यवसाय	0	00	19	100
4	दैनिक उपभोग वस्तु विक्रय सम्बन्धित व्यवसाय	0	00	12	100
5	सेवा सम्बन्धित व्यवसाय	2	14.28	12	85.72

(स्त्रोत् – प्राथमिक आंकड़े) सारणी से स्पष्ट हैं कि केवल 6 फुटकर व्यापारी पी.ओ.एस. मशीन एवं मोबाइल बैंकिंग के पक्षधर हैं, एवं 118 इनके उपयोग के पक्ष में नही हैं।

अध्ययन से ज्ञात होता हैं कि रायपुर नगर के फुटकर व्यापारी, भारत के नकदरहित समाज बनने के पक्षधर नही हैं, यह स्थिति संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची, एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर आधारित केवल रायपुर शहर के फुटकर व्यापारियों के तथ्य हैं। यह स्थिति भारत के महानगर अथवा अन्य बड़े शहरों में विभिन्न हो सकती हैं।

सारणी कमांक 05

वर्णनात्मक सांख्यिकी

क.	विमुद्रीकरण के प्रभावित चर	औसत	प्रमाप विचलन	विचलन गुणांक
1	राष्ट्र की अर्थव्यस्था में कमी	2.45	1.122	0.474
2	विमुद्रीकरण का समर्थन	4.03	1.089	-1.063
3	विमुद्रीकरण के कियान्वयन में समस्या	4.24	1.171	-1.534
4	विवाह के लिए अपर्याप्त प्रावधान	4.02	1.281	-1.091

अध्ययन से ज्ञात होता हैं कि उत्तरदाता विमुद्रीकरण के प्रभावित चरों में फुटकर व्यापारी, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कमी कें असमर्थक हैं (औसत 2.45), विमुद्रीरण के निर्णय का समर्थन करते हैं (4.03), विमुद्रीकरण के क्रियान्वयन में समस्या के पक्ष में हैं (औसत 4.24), तथा विमुद्रीकरण के क्रियान्वयन में विवाह के लिए अपर्याप्त प्रावधान का भी समर्थन करते हैं (औसत 4.02) ।

7. निष्कर्ष

अध्ययन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर के फूटकर एवं सीमांत व्यापारियों पर केंन्द्रित विमुद्रीकरण के प्रभाव पर आधारित हैं। अध्ययन में प्राप्त तथ्यों सें निष्कर्ष निकलता हैं कि फूटकर एवं सीमांत व्यापारी केवल जीवन यापन एवं पारिवारिक मुल

आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आपना व्यवसाय का संचालन करते हैं। जिनकी आमदनी का अधिकांश भाग उनके व्यवसाय संचालन में ही व्यय हो जाता हैं। ऐसे में विमुद्रीकरण के निर्णय ने फूटकर एवं सीमांत व्यापारियों के व्यवसाय को प्रभावित किया, जिनका असर समाजिक रूप से भी उनके जीवन प्रणालियों को प्रभावित किया हैं, अध्ययन से ज्ञात हुआ हैं कि फूटकर व्यापारी विमुद्रीकरण के निर्णय का समर्थन तो करते हैं, परन्तु विमुद्रीकरण के क्रियान्वयन ने उन्हे नकरात्मक स्वरूप सें स्पष्ट करवाया, विमुद्रीकरण के क्रियान्वयन में अधिकांश समस्या चिल्हरों की कमी व 2000 रूपयें के बड़े नोटों के प्रचलन से हुआ। साक्षात्कार के दौरान फुटकर व्यापारियों ने चिल्हरों की कमी के कारण ग्राहकों को मना करने की बात भी बतलाई। विमुद्रीकरण के उद्देश्य कैशलेस (नकदरहित) समाज बनाने के संदर्भ में अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकलता हैं कि रायपुर शहर के फुटकर व्यापारी, कैशलेस समाज के पक्षधर नही हैं। क्योंकि वे अधिकांशतः अशिक्षित हैं या आंशिक रूप से शिक्षित हैं अतः वे वर्तमान नवीन तकनीकी एवं बैंकिंग प्रणालियों से अवगत नही हैं। तथा उन्हे नकद व्यवसाय की आदत हो गई हैं, एवं वें पुराने प्रणालियों को ही उचित समझते हैं एवं उसमें परिवर्तन नही चाहते।

Reference and Notes

1. Ambedkar, B.R. (1923). The Problem of the Rupee : It's Origin and it's Soulation (History of Indian Currency and Banking); *Great Britain by Bulter and Tanner Ltd..* Landon, Chapter.2 pp. 104.
2. Gawali, S.D. (2017). Historical Background and Demonetization on Indian Economy; *Vidyabharti International Interdisciplinary Research Journal.* Amravati. Vol. 6, Special Issue. 1, pp.207-211.
3. Echekoba, F.N, and Ezu, G.K. (2012). Electronic Retail Payment System : User Acceptability & Payment Problem in Nigrria; *Journal of Business & Management Review*, Vol. 5, pp. 60-63.
4. Maduri, U., Srinivasa, D., and Naga Veni, P. (2016). Making India a Cashless Economy; *International Journal of Academic Research,* Vol.3, Issue. 12(4), pp. 22-24.
5. Radha Krishna, T. (2016). India is a Cashless Economy; ibid, pp. 141-145.
6. Chelladuri, M., and Sornaganesh, V. (2016). Demonetisation : Unified Payment Interface & Cashless Economy; *International Journal of Informative & Futuristic Research.* Vol.4, Issue. 3, pp. 5654-5662.
7. Rajkumar, Dennis,J., and Shetty, S.L. (2016). *Economic and Political Weekly,* Vol.51(48), pp.13-17.
8. Nag, A. (2016). Lost due to Demonetization, ibid, pp.18-21.
9. Dasgupta, D. (2016). Theoretical Analysis of Demonetization; *Economic and Political Weekly,* Vol.51, No.51, Dec 2016, pp.67-71.
10. Wakins, P. (2017). Demonetization Through Segmented Markets : Some Theoretical Perpective, Vol. 52, No.9, March 4,2017.
11. Methta, S.N. (2016). Demonetisation Worst Effected The Small Traders; *International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science,* Vol.5, Issue. 12, Dec.2016, pp.52-58.
12. Tandale, P.G., Gaikwad, A.T., and Marathe, R.A. (2017). Study on Scope of Internet Banking Services in Kolhapur City; *International Journal in Multidisciplinary and Acadamic Research.* Vol. 6, No.1, pp.1-5.
13. Livingstone, G.D. (2016). Socio-Economic Dimension of Demonetization in India; *International Journal of Academic Research.* Vol. 3, Issue 12(4). pp.77-83.
14. Durga, G., and Durga Devi, A.U. (2016). The Socio Economic and Political Impacts of Demonetization in India; ibid. pp121-123.
15. Ramamurty, S.S. (2016). Socio Economic Dimensions of Demonetization in India; ibid. pp138-140.
16. Mahajan, P. (2017). Effect of Demonetization on Financial Inclusion in India; 6th International Conference on Recent Trends in Engineering, Science & Management, 8 jan 2017. pp. 1282-1287.
17. Bharathi, K. (2017). Demonization : Impact on India Ecomony; *International Journal of Trend in Research and Development.* pp. 10-23.
18. Preety (2017). The Benefits and Challenges or Demonetisation in India; *International Journal of Emerging Tec. in Engineering Research,* Vol.5, Issue. 2, pp.22-27.
19. Sing, S. (2017). Impact of Demonetizing in Indiua Economy : Issues and Challenges; *International Journal in Management and Social Science,* Vol.5, Issue. 1, pp.14-23.
20. Rai, D. (2016). Aftermath of Demonetization on Rural Population; *International Journal of Research in Economics and Social Science,* Vol. 6, Issue. 11, 11 Nov 2016, pp.223-228.
21. Nerker, A.D. (2016). Demonetisation : Impact on Indian Economy; *International Journal of Advanced Engineering and Science,* Vol. 3, Issue. 12, Dec 2016, pp. 281-283.
22. Bansal, J. (2017). International Conference on Innovative Research in Science, Technology and Management, 22nd -23rd jan 2017.
23. Kahlan, A.K. (2017). 6th International Conference on Recent Trends in Engineering, Science & Management 8th jan 2017.
24. Rathore, S.V. (2013). Demonetisation : Impressions on India Agriculture; Vol.3(2). pp.88-89.
25. Rani, G. (2016). Effect of Demonetization on Retail Outlets; *International Journal of Applied Research.* Vol.2(12). pp.400-401.
26. Balamurugan, S. and Hemalatha, B.K. (2016). Impact of Demonetization : Organized and Unorganized Sector; *IOSR Journal Humanities and Social Science,* pp.1-11.

27. Kumar, N., and Sarmila (2016). Demonetisation and It's Impact on Indian Economy; *QEST: International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Science.* Vol. 4, Issue. 12, pp.23-26.

28. Kalyani, P. (2016). An Empirical Study of The Effect of Demonetization in India in The year 2016 and Analyzing Shifting Trends in Marketing/Purchasing to the Alternative Options; *Journal of Management Engineering and Information Technology,* Vol.3, Issue.6, Dec.2016. pp.20-34.